



धौलपुर में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुई भाजपा की जनाक्रोश सभा में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। सभा को राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़, पूर्व मंत्री मदन दिलावर तथा भाजपा सांसद मनोज राजोरिया ने संबोधित किया।

‘पेपर लीक करने वालों पर योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोज़र चलना चाहिए’

धौलपुर में हुई जनाक्रोश सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ ने यह भी कहा कि, दलित अत्याचार में राजस्थान, भारत में दूसरे नम्बर पर है

धौलपुर, 30 दिसम्बर (निस)। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव पहाड़ी मरैना पीतम गिरी बाबा पर आज शुक्रवार को भाजपा की जनाक्रोश सभा आयोजित की गई। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं पूर्व मंत्री मदन दिलावर, सांसद मनोज राजोरिया एवं भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने सभा को संबोधित किया।

राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोज़र चलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि दलित अत्याचार में राजस्थान भारत में दूसरे

■ सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मदन दिलावर ने गहलोत सरकार को अली बाबा और चालीस चोरों की सरकार बताया।

नम्बर पर है, किसानों का अपमान हो रहा है, धौलपुर जिला परिवहन विभाग की अवैध वसूली निरंतर जारी है। धौलपुर की जनता के साथ किया गया अन्याय सूद सहित वसूला जाएगा। पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में गोवंश की बहुत ही दुर्दशा है, एक

विशेष वर्ग को बचाया जा रहा है, मंदिर तोड़ने में राजस्थान की गहलोत सरकार सबसे आगे है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, सिर्फ रात्रि में ही सीमित समय के लिए बिजली मिल रही है, राजस्थान में अलीबाबा चालीस चोर की सरकार है। एक सर्वे के अनुसार राजस्थान में 70 फीसदी लोग रिजर्व देकर अपना काम करवा रहे हैं।

सांसद मनोज राजोरिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को यहां के विधायक अपना बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।

जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि वह दिन दूर नहीं कि धौलपुर

की चारों सोंटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठेंगे और राज्य में भारी बहुमत से मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आएगी।

वर्मा ने आंगतुकों को धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर जन आक्रोश यात्रा प्रभारी हेमेंद्र विशिष्ठ, सह संयोजक सोवरण सिंह गलेथा, जयवीर पोशवाल, नागवेंद्र सिंह, मरैना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, विश्वम्भर दयाल शर्मा, सतेंद्र पाराशर, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ.विष्णु शर्मा, रामवीर शर्मा, भूपेंद्र चुरईया, बाँबी परमार, पंडित मधुसूदन शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, हरिनवास प्रधान, कुकनू शर्मा, दुष्यंत शर्मा, शिवशंकर परिहार आदि उपस्थित रहे।

‘विवाद सुलझाने के लिए आया हूँ फाइव स्टार में बैठने के लिए नहीं’

राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट-गहलोत विवाद पर अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट की

जयपुर, 30 दिसम्बर (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 3 दिन से जयपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने जयपुर में कांग्रेस के सभी विधायकों, विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी तथा सहित मंत्री परिषद से चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और स्पीकर डॉ. सी.पी. जोशी से उनके निवास पर जाकर चर्चा की है। इसी के साथ उन्होंने अग्रिम संगठन के नेताओं से भी मिलकर फीडबैक लिया है। इस कवायद के बाद में उम्मीद जगी है कि पार्टी में सत्ता और संगठन में जो नियुक्तियां बाकी हैं, उन पर जल्द ही निर्णय हो जाएगा। वहीं जिन बातों को लेकर नाराजगी है, उन्हें भी दूर किया जाएगा। 3 दिन तक की इस फीडबैक कवायद के दौरान सबसे बड़ी बात यही उभरकर आई है कि अधिकांश नेता और कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की जो तनावनी है, उसे समाप्त किया जाना जरूरी है। सभी नेताओं से फीडबैक लेने के बाद रंधावा ने मीडिया से बात की और पायलट-गहलोत विवाद पर कहा कि राजस्थान में नेताओं के बीच चल रहा विवाद सुलझाना उनका काम है। वो यहां फाइव स्टार में बैठने के लिए नहीं आए हैं। उनका काम लोगों के बीच

■ रंधावा से मिलकर रघु शर्मा ने कहा- “कार्यकर्ता आलाकमान और संगठन के प्रति निष्ठा रखें, व्यक्तिगत निष्ठा से पार्टी नहीं चलती।”

■ रंधावा ने संगठन के बारे में कहा कि, उनका पहला टारगेट जिला, ब्लॉक व कार्यकारिणी में नियुक्तियां करना है, जो वो अगले दो दिन में पूरा कर लेंगे।

बैठना व उनकी समस्याओं का निराकरण करना है, ताकि आगे किसी भी प्रकार की समस्या शेष न रह जाए।

उन्होंने आगे कहा कि अभी उनका पहला टारगेट राजस्थान में जिला, ब्लॉक व प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में नियुक्तियां करना है। इस काम को वो अगले एक-दो दिन में पूरा कर लेंगे। रंधावा ने कहा कि अभी वो विधानसभा का टिकट देने नहीं आए हैं। फिलहाल वो संगठन का काम करने आए हैं और वैसे भी विधानसभा चुनाव में टिकट सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे। सफिक हाउस में कई नेताओं - कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद रंधावा ने पत्रकारों से कहा कि वे पिछले दो दिन से लगातार कांग्रेस

कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर फीडबैक ले रहे हैं। ऐसे में एक-दो दिन में जिला, ब्लॉक व राज्य स्तरीय संगठन में शेष बची नियुक्तियों को वो पूरा कर देंगे।

इस बीच रंधावा से मिलने के बाद पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राजनीतिक पार्टी में कार्यकर्ता को आलाकमान और संगठन के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत निष्ठा से पार्टी नहीं चलती है। शर्मा ने कहा कि रंधावा सुलझे हुए व अनुभवों से भरे हैं, लेकिन वे कांग्रेस की सियासत को लेकर उनकी बातचीत हुई है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि वो प्रदेश की उम्मीद सियासी परिस्थितियों को बहुत जल्द सुलझा लेंगे।

क्या “होनहार पुत्र” गुलाम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के रूप में जम्मू कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारचन्द का नाम लिया जा सकता है जो कांग्रेस छोड़कर आजाद की पार्टी में शामिल हुये थे। तारचन्द ने अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी छोड़ दी है। कांग्रेस से आजाद के संबंध-विच्छेद का अन्त बहुत तित्कालपूर्ण रहा था, क्योंकि इस वरिष्ठ नेता ने पार्टी नेतृत्व तथा खासतौर से राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। सोनिया गांधी को लिखे गये कड़े-प्रहारों से परे पाँच पृष्ठों

के उस त्याग पत्र में, उन्होंने सोनिया गांधी को “नाम मात्र का अध्यक्ष” कहा था, जिनके नाम पर निर्णय लेने का काम राहुल गांधी या उनके पी.ए. तथा सिक्वोरिटी गार्ड करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को भी “नॉन-सीरियस तथा अपरिपक्व व्यक्ति” बताया था।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव, जो 2023 में हो सकते हैं, के अवसर पर, कांग्रेस नेतृत्व अतीत की इन तुच्छ बातों को भूलने तथा माफ कर देने के लिये तैयार हो सकता है, बशर्ते कि

अपनी सोच में कुछ सुधार लायें। कांग्रेस के रणनीतिकार ऐसा मानते हैं कि ऐसी पूरी-पूरी संभावना दिखाई दे रही है कि जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों में आजाद की पार्टी की मौजूदगी से, विशेषकर जम्मू क्षेत्र में गैर-भाजपा वोट बंटेंगे, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। समझा जाता है कि अम्बिका सोनी ने आजाद को सलाह दी है कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों तथा राहुल गांधी के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें।

प्र.मंत्री मोदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) में पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनशील धनखंड ने एक बयान में कहा कि वह सरलता की प्रतिमूर्ति और माँ की ममता का प्रतीक थीं-उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की माँ हीरा बा के निधन से गहरे दुःख में हूँ।

बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष को पार्टी ने निष्कासित किया

भाजपा का आरोप है कि राजीब रंजन नीतीश कुमार से नजदीकी बढ़ा रहे थे तथा अवसर पार्टी विरोधी बयानबाजियां कर रहे थे

पटना, 30 जनवरी। बिहार भाजपा ने अनुशासनहीनता के लिए अपने एक उपाध्यक्ष राजीब रंजन को निर्लंबित कर दिया। पार्टी ने राज्य इकाई के प्रमुख संजय जायसवाल का 29 दिसंबर को जारी एक पत्र साझा किया। हालांकि, इसके तुरंत बाद रंजन ने दावा किया कि उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से खुद ही इस्तीफा दिया है। गौरतलब है कि, राजीब रंजन नीतीश के करीबी लोगों में से एक रहे हैं माना जा रहा है कि, इन दिनों वे चोरी छुपे नीतीश से एक बार फिर नजदीकियां बढ़ा रहे थे। भाजपा को इस बात की पहले से ही भनक लग चुकी थी उनको बार-बार चेतावनी भी दी गई थी।

बिहार भाजपा अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा कि राजीब रंजन को मौखिक रूप से चेतावनियां दी गई थीं पर वो उनकी अनदेखी करते हुए पार्टी लाइन के विपरीत बयान दे रहे। जायसवाल ने इसके लिए उन्हें फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हुए राजीब के बयान अशोभनीय हैं। ये और पार्टी की प्रतिष्ठा पर भी गलत असर डालते हैं।

उन्होंने कहा कि राजीब रंजन को उनके पद से मुक्त कर छह साल के लिए पार्टी से निलंबित किया जाए है। खास बात यह है कि भाजपा ने शुक्रवार दोपहर तक इस पत्र को सामने नहीं रखा। उसने इसे तब जारी किया, जब रंजन ने एक

बयान जारी कर आरोप लगाया कि पार्टी दलितों और ओ.बी.सी. के प्रति अच्छा रवैया नहीं रखती है। राजीब रंजन ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे से भटक गई है। बिहार में एजेंडा पटना केन्द्रित हो गया है। उनके पैतृक जिला नालंदा भी भाजपा के लिए दोगम दर्जे की जगह है। बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है वो उनकी समझ से परे है। पार्टी के अंदर का यह घमासान ऐसे समय में सामने आया है, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा 3 जनवरी को प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। राजीब रंजन, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाइटेड) के साथ रहे हैं।

ओ.बी.सी. आरक्षण लागू करवाने की जद्दोजहद में योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची

योगी सरकार चाहती है कि, निकाय चुनाव से पहले ओ.बी.सी. आरक्षण लागू हो जाये ताकि इसका पार्टी राजनीतिक लाभ ले सके

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (वार्ता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय के चुनावों में अन्य पिछड़ी जातियों (ओ.बी.सी.) को आरक्षण देने के प्रावधान वाली अधिसूचना रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को नुतिपूर्ण करार देते हुए गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय

■ गौरतलब है कि, निकाय चुनाव में ओ.बी.सी. आरक्षण की घोषणा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गत दिनों रोक लगा दी थी।

की लखनऊ पीठ ने 27 दिसंबर के अपने फैसले में ओ.बी.सी. आरक्षण के प्रावधान को रद्द करते हुए राज्य सरकार को बिना ओ.बी.सी. आरक्षण तत्काल

चुनाव कराने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने राज्य के कई नगर पालिकाओं के कार्यकाल 31 जनवरी 2023 को समाप्त होने के तथ्य पर जोर

करते हुए बिना ओ.बी.सी. आरक्षण तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में राज्य सरकार ने तर्क देते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय ने स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव में ओ.बी.सी. के लिए सीटों में आरक्षण के प्रावधान संबंधी 5 दिसंबर की अधिसूचना के प्रारूप को रद्द नहीं कर सकती।

कोटपूतली में तोड़-फोड़ की कार्यवाही पुनः शुरु?

कोटपूतली, 30 दिसम्बर। (निस)। स्थानीय नगर परिषद द्वारा कोटपूतली के मास्टर प्लान 2011-31 व रियासतकालीन (खेतड़ी टिकाना) के नक्शे अनुसार सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निरन्तर संरचनाओं को हटाने का कार्य किया जा रहा है।

गौरतलब है कि विगत अगस्त माह में परिषद द्वारा मुख्य चौगहे से पुरानी नगर पालिका तिराहे तक सड़क की चौड़ाई 80 फीट व पूतली कट से बानसपुर मोड़ खण्ड के सरदार स्कूल से शनि मंदिर तक की सड़क को 60 फीट चौड़ा करने की कार्यवाही शुरू की थी। जिसमें अब तक 95 फीसदी से अधिक निर्माण हटाये जा चुके हैं।

परन्तु नगर परिषद द्वारा नोटिस नहीं दिये जाने के संबंध में कई मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। हाल ही में न्यायधीन एस. एन . श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद भारवनानी की खण्ड पीठ ने कोटपूतली नगर परिषद आयुक्त

■ इस मामले में हाई कोर्ट में वर्ष 2022 में 40 से अधिक याचिकाएँ दायर की गई थीं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि, अगस्त माह में की गई तोड़-फोड़ की कार्यवाही से पहले उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था और उनकी आपत्तियों की कोई सुनवाई नहीं की गई थी।

■ बिना नोटिस दिये कार्यवाही करने के कारण हाई कोर्ट में सभी अवमानना याचिकाएँ लंबित हैं, जिसमें नगर परिषद आयुक्त से जवाब तलब किया गया है।

■ किंतु, कोटपूतली में एक अन्य सड़क पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही शुरू किये जाने की सूचना से नगरवासी हैरान हैं और आक्रोश का माहौल है।

फतेह सिंह मीणा को नवम्बर में ही इस मामले में जवाब तलब किया था और पूछा था कि क्यों नगर परिषद ने तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने से पूर्व मकानों और दुकानों के मालिकों को पूरा नोटिस भेजकर उनकी आपत्तियों पर सुनवाई क्यों नहीं की।

जैसा कि विदित है कि, हाईकोर्ट ने इस संबंध में सुनवाई करते हुए विगत 25 फरवरी 2022 को तत्काल कोटपूतली नगर पालिका को आदेश दिये थे कि, वह सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस भेजकर उनकी आपत्तियां सुने और उसके पश्चात ही कोई कार्यवाही

करे। अदालत ने तत्कालीन नगर परिषद को कहा था कि, सम्पत्ति मालिकों के दस्तावेज जांच कर कार्यवाही के बाबत स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के लिए कहा गया था। परन्तु, हाई कोर्ट में करीब 40 से अधिक याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, वर्तमान नगर परिषद ने हाई कोर्ट के आदेशों को पालना नहीं की और अगस्त माह में फिर से तोड़-फोड़ की कार्यवाही की और किसी भी याचिकाकर्ता को सुनवाई के लिए नोटिस जारी नहीं किये थे। इन मामलों से जुड़ी अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट में जनवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल, परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा के मुताबिक जिन लोगों द्वारा निर्माण नहीं हटाये जायेगे, उनके निर्माण नगर परिषद द्वारा हटाया जाकर ज़ुमाना वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

पिता पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) स्थित पिता के घर छोड़ा था। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद याचिकाकर्ता और उसके पिता ने मुकेश कुमार को कई बार कहा कि, वह उन्हें वापस ले जाए। इसके बावजूद भी मुकेश उन्हें लेने नहीं आया। याचिका में कहा गया कि, गत सात दिसंबर को मुकेश कुमार घर के बाहर खेल रहे दोनों बच्चों का अपहरण कर अपने साथ ले गया और उन्हें बंधक बना लिया। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने गुप्तसूचना के लिए अपने में परिवार दिया, लेकिन पुलिस ने उसे दर्ज नहीं किया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की संतानों को उसके पिता से रिहा कराया जाए सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मुकेश कुमार को नोटिस जारी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता को दोनों बच्चों को दस जनवरी को अदालत में पेश करने को कहा है।

1979 में इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस के पास केवल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) खिलाफ अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से तथा खुले आम अपशब्दों का प्रयोग किया हो, लेकिन केन्द्रीय नेतृत्व ने गहलोत ने डॉट-फटकार तक नहीं लगाई।

विधानसभा चुनावों में अब एक साल से कम समय रह गया है तथा बुरी तरह से बँटै हुई भाजपा को केवल इस एक ही बात का सहारा है कि गांधी परिवार अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बना रहने दे। यह स्थिति भाजपा नेतृत्व के अनुकूल रहेगी क्योंकि

गहलोत मुख्यमंत्री रहते, भाजपा अपनी आसान जीत के प्रति आश्वस्त है। इस साल ने गहलोत को प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने समबंध सुधारते भी देखा है। यह वर्ष इस बात का भी साक्षी है कि अडानी ग्रुप, संभवतः नरेन्द्र मोदी के लगातार निवेश पर सहमति बन गई थी।

घोर आश्चर्य की बात यह रही कि राहुल गांधी, जो अम्बानी एवं अडानी के कटु आलोचक हैं, ने गौतम अडानी द्वारा अशोक गहलोत के साथ हाथ

मिलाने पर कोई खास टिप्पणी तक नहीं की। अच्छे इरादों तथा निर्दिष्ट इरादों वाला रास्ता अपार दौलत ही प्रशंस किया करती है। राहुल गांधी भले ही नैतिकता पर कितने ही भाषण देते हैं, कितने ही ट्वीट करते हों, लेकिन वे भी दौलत के इस प्रकरण में अपवाद नहीं हैं।

गहलोत के नेतृत्व में, पार्टी ने कोई भी चुनाव नहीं जीता है लेकिन फिर भी पार्टी उनके खिलाफ कदम उठाने से डरती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बनकर रह गई है, जिसका नेतृत्व ऐसे चतुर्कारों

और चापलूसों से घिरा रहता है, जो स्वयं तो कोई चुनाव जीत नहीं सकते, लेकिन नेतृत्व को यह सलाह जरूर देते रहते हैं कि चुनाव कैसे (नहीं) जीता जाता है। गहलोत के कुशासन तथा गांधी परिवार के कमजोर नेतृत्व का खामियाजा एवं आघात जितना राजस्थान ने भुगाता है, उतना किसी अन्य राज्य ने नहीं भुगाता।

अगर एकाएक तथा जबरदस्त सर्जरी नहीं की गई, तो ऐसे हालात के चलते अगले वर्ष कांग्रेस पार्टी सर्वनाश की स्थिति तक पहुँच जायेगी।

सरकार दो लाख मेगा डेयरियां खोलेगी देश में

माँड्या, 30 दिसंबर (वार्ता)। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि तीन साल में ग्रामीण स्तर पर दो लाख प्राथमिक डेयरियां स्थापित कर भारत दुग्ध क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बनकर उभरेगा।

शाह ने यहां मेगा डेयरी का उद्घाटन करने के बाद कहा कि तीन साल में देश भर में ग्रामीण स्तर पर दो लाख प्राथमिक डेयरियां स्थापित की जाएंगी, जिसके